Business Standard, ND, Dated 11.1.12

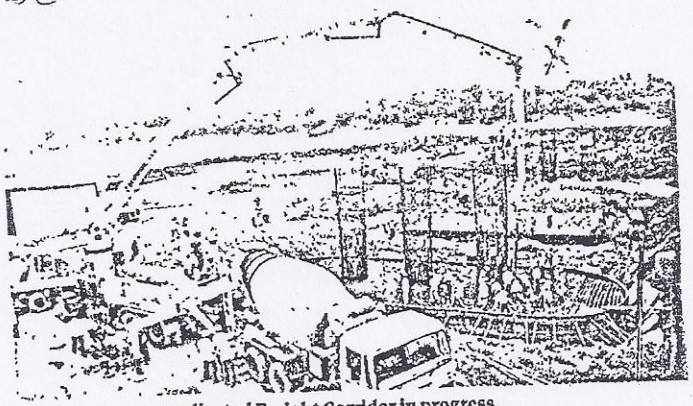

Work on Western Dedicated Freight Corridor in progress.

Rail freight corridor sees global contest

DISHA KANWAR
New Delhi, 10 January

A ₹6,000-crore railway tender for the Khurja–Bhaupur section of 343 km on the eastern Dedicated Freight Corridor (DFC) has had global construction companies vying to win it.

Sixteen entitites shortlisted in the pre-qualification stage include China Railway First Group, a part of state-owned China Railway Engineering Corporation, in consortium with Soma; Larsen & Toubro; Spanish companies Corsan and OHL, Turkey-based Alarko and Malaysia's Leighton. They've all bid for the civil structure and track work contracts.

Consequent to this shortlisting, there will be a process of Request For Proposal (RFP) for the financial bidding. The final selection is expected by October-end. "The pre-qualification bid for the Rewari-Iqbalgarh section (625 km) in the western corridor has also been invited and we are expecting to finalise the results by February-end 2012," said a DFC Corporation official. DFCC is the company set up, in 2006, under the ministry of railways to get the corridors through.

The Bhaupur–Khurja section is part of the Ludhiana-Mughalsarai stretch in the eastern corridor. The stretch has been divided into three sections. In this one of 343 km, around 234 km is parallel to the existing tracks and there is a detour of around 110 km.

There will be a phased commissioning of various sections, with 66 km of the 122-km Mughalsarai-Sonnagar section on the eastern corridor ready by December 2013.

DFCC has acquired around 52 per cent of the land. The total land required in the eastern and western corridors is around 10,000 hectares.

Business Standard, ND, Date 13.1.12

रेल लाइन बिछाने की होड़ में विदेशी कंपनियां

दिशा कंवर
नई दिल्ली, 12 जनवरी

निर्माण क्षेत्र की अग्रणी वैश्विक कंपनियां 6,000 करोड़ रुपये के खुर्जा-भावपुर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (343 किलोमीटर लंबी) की निविदा के लिए होड़ में हैं। इसके लिए पहले चरण में जिन 16 कंपनियों का नाम छांटा गया है उनमें चाइना रेलवे फर्स्ट ग्रुप, लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी), स्पेन की कंपनी कोर्सन और ओएचएल, तुर्की की अलार्को और मलेशिया की लिफ्टॉन के नाम शामिल हैं। इन कंपनियों ने इस खंड में बुनियादी ढांचा और आमान (पटरी बिछाने) का कार्य अनुबंध के लिए बोली लगाई है।

इन कंपनियों में कुछ नाम फिर छांटे जाएंगे और उसके बाद वित्तीय बोली के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में कंपनियों का अंतिम चयन अक्टूबर 2012 के अंत तक होने की संभावना है। इस बारे में डीएफसीसी के एक अधिकारी ने कहा, 'पश्चिमी कॉरिडोर में रेवाड़ी-इकबालगढ़ खंड (625 किमी) के लिए भी पहले चरण के तहत बोलियां आमंत्रित की गई हैं। हमें उम्मीद है कि फरवरी 2012 के अंत तक हम इसे अंतिम रूप दे देंगे।' पूर्वी कॉरिडोर के तहत लुधियाना-मुगलसराय के बीच आने वाले भावपुर-खुर्जा खंड को 3 खंडों में बांटा गया है। 343 किलोमीटर में से 234 किलोमीटर मौजूदा पटरी के समानांतर है और करीब 110 किलोमीटर अलग रास्ता है।

कार्य में तेजी

- लुधियाना-मुगलसराय खंड के लिए वित्त की व्यवस्था विश्व बैंक की मदद से की जाएगी
- पूर्वी कॉरिडोर में खुर्जा से भावपुर खंड के लिए पहले चरण में 16 कंपनियों का नाम छांटे जा चुके है

Hindustan, ND, Dat 16.1.12

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण फास्ट ट्रैक पर

नई दिल्ली | अरविंद सिंह

रेलवे की सबसे महत्वकांक्षी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) परियोजना फास्ट ट्रैक पर है। अधिकारियों का दावा है कि पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पूरी होंगी। औसतन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेंगने वाली मालगाड़ियां मार्च 2017 तक डीएफसी रूट पर 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में बातें करेंगी।

मालगाड़ियों की लोड ढोने की क्षमता भी दोगुनी हो जाएगी। जिससे देश के आयात-निर्यात उद्योग में दस गुना का जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी डीएफसी फेज-1 के वड़ोदरा से रेवाड़ी सेक्शन के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जायका) से मार्च 2010 में 4500 करोड़ रुपये का कर्ज पहले ही मिल चुका है। इस सेक्शन पर निर्माण कार्य चल रहा है।

इसके अलावा फेज-2 के मुंबई से वड़ोदरा और रेवाड़ी से दादरी सेक्शन के लिए 11,500 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त मार्च 2012 तक मिलने की संभावना है। जायका परियोजना की लागत का 80 फीसदी कर्ज देगा जबकि शेष राशि रेलवे जुटाएगा। इसी कड़ी में, पूर्वी डीएफसी परियोजना विश्व बैंक की आर्थिक मदद से पूरी की जा रही है। परियोजना की लागत का 67 फीसदी धन विश्व बैंक देगा। शेष राशि रेलवे पीपीपी मोड से जुटाएगा। विश्व बैंक मई 2011 में 973 मिलियन डॉलर कर्ज की मंजूरी पहले ही दे चुका है।

2017 तक होगी शुरू

- मालगाड़ियां मार्च 2017 तक डीएफसी रूट पर 100-150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी
- पश्चिमी डीएफसी के लिए मार्च तक जापान से 11,500 करोड़ कर्ज मिलने की उम्मीद
- मालगाड़ियों की लोड क्षमता होगी दोगुनी, आयात-निर्यात उद्योग में आएगा 10 गुना उछाल

करोड़ों रुपये की लागत

- 1514 किलोमीटर लंबे मुंबई-वड़ोदरा-रेवाड़ी-दादरी सेक्शन (पश्चिमी डीएफसी) पर कुल 38,503 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है
- 1839 किलोमीटर लंबे लुधियाना-दादरी-कानपुर-मुगलसराय-सोननगर-दानकुनी सेक्शन पर 39,127 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है
- इसमें 4,200 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के मुआवजे पर खर्च होंगे।
- माल ढुलाई के लिए पृथक रूट होने पर दिल्ली-मुंबई व दिल्ली-हावड़ा रूट पर अधिक संख्या में यात्री ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। साथ ही इस रूट पर कंजेशन की स्थिति समाप्त होगी
- दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा रूट पर दो दशक तक सुगमता से होगी माल ढुलाई, रेलवे की कमाई में होगा भारी इजाफा

विश्व बैंक देगा मदद

- इसी कड़ी में पूर्वी डीएफसी परियोजना विश्व बैंक की आर्थिक मदद से पूरी की जा रही है। परियोजना की लागत का 67 फीसदी धन विश्व बैंक देगा।

Business Line ND 31 Jan 2012 p-1

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR

Sojitz-Ircon, Mitsui-L&T in race for Rs 9,000-cr project of western arm

Mamuni Das

New Delhi, Jan. 30

Two bidders, both led by Japanese companies, are in the race for a Rs 9,000-crore contract that is part of the dedicated freight corridor. One is a consortium of Sojitz Corporation-Ircon and the other Mitsui-Larsen & Toubro.

Both these companies are at the pre-qualification stage for 625 km of civil work on the Rewari-Iqbalgarh/Palanpur section, which forms part of the Western Corridor.

This project will form part of the Rs 15,000-crore worth of contracts the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd will award in the next financial year.

Bidders have to rope in a Japanese partner as the project is funded by the Japan International Cooperation Agency, which mandates a Japanese lead partner.

The Western Corridor — which is a track from JN Port in Maharashtra to Dadri in Uttar Pradesh — covers 1,483 km.

The traffic on this corridor is expected to mainly comprise containers from western ports of JN Port, Mumbai, Pipavav, Mundra and Kandla to container depots located in northern India.

The Western Corridor — which is a track from JN Port in Maharashtra to Dadri in Uttar Pradesh — covers a distance of 1,483 km.

The Eastern corridor — linking Ludhiana in Punjab with Dankuni in West Bengal — covers 1,800 km

EASTERN CORRIDOR

For the civil work of the 343-km Khurja-Bhaupur section, which is part of the Eastern Corridor, the shortlisting has been done. The bidders include China Railway First Group-Soma, Corsan-Kalindi-C&C, Alarko-NCC and HCC-Alstom.

The Eastern Corridor is the World Bank arm of the dedicated freight corridor. "We aim to award these contracts by the quarter-ending September in 2012-13," the official said.

WORLD BANK LOAN

The World Bank has signed a loan agreement of $975 million for funding a part of the Eastern Corridor.

The 1,800-km Eastern Corridor — linking Ludhiana in Punjab with Dankuni in West Bengal — will cater to a number of traffic streams — coal for the power plants in the northern region of Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Punjab and parts of Rajasthan from the Eastern coal fields, finished steel, foodgrains, cement, fertilisers, limestone from Rajasthan to steel plants in the east and general goods.

mamuni@thehindu.co.in

Hindustan, ND, Dat 04.03.12

दिसंबर 2013 में मुगलसराय-सोननगर के बीच 100 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी मालगाड़ियां

डीएफसी से मालगाड़ियां भरेंगी फर्राटा

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

रेलवे की मेगा परियोजना डीएफसी (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) पर दिसंबर 2013 तक मालगाड़ियों के फर्राटा भरने की तारीख तय हो गई है।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सीधी निगरानी के कारण ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर निर्धारित समय से दो साल पहले ही मालगाड़ियां 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेंगी। डीएफसी परियोजना में तेजी लाने के इस प्रयास को 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। रेलवे ने पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडार परियोजना के मुगलसराय-सोननगर सेक्शन (66 किलोमीटर) पर सबसे पहले मालगाड़ी दौड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए 31 दिसंबर 2013 तारीख निर्धारित की गई है। हालांकि इस सेक्शन पर 15 जुलाई 2015 तक मालगाड़ी चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फरवरी में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों व डेडिकेडेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। यही कारण है कि एफसीसीआईएल ने उक्त सेक्शन पर दो साल पहले ही मालगाड़ी चलाने की घोषणा की है।

पश्चिमी डीएफसी परियोजना के 50 किलोमीटर लंबे वालसद-बेस्तन सेक्शन पर भी दिसंबर 2013 तक मालगाड़ियों को चलाने की कोशिशें तेल हो गई हैं। एफसीसीआईएल के एमडी आर.के. गुप्ता ने 'हिंदुस्तान' को बताया कि मुगलसराय-सोननगर सेक्शन के लिए 3500 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं।

परियोजना का हाल

- वर्तमान में मालगाड़ियों की औसतन रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा ह
- 2007 में डीएफसी की अनुमानित लागत 2800 करोड़ रुपये थी।
- लेटलतीफी के कारण अनुमानित लागत 82 हजार करोड़ हो गई है
- पूर्वी-पश्चिमी डीएफसी परियोजना के तहत कुल 3300 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी
- मालगाड़ियों का एक्सल लोड 32 से 35 टन हो जाएगा। वर्तमान में मालगाड़ियों का एक्सल लोड सिर्फ 22 टन है
- रेलवे की 90 फीसदी मालढुलाई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर होगी
- डीएफसी बनने के बाद दिल्ली-हावड़ा, दिल्ली-मुंबई रूट पर यात्री ट्रेनों को कंजेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रेनें समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी

डीएफसी को आगे बढ़ाने के लिए यूपी तैयार

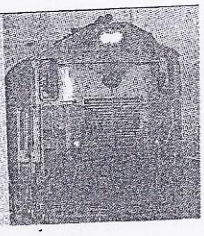

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहल के पश्चात सबसे पहले उत्तर प्रदेश डीएफसी परियोजना की निगरानी समिति गठित करने में तेजी दिखाई है। प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में 23 फरवरी को निगरानी समिति का गठन कर दिया गया है। समिति में राजस्व सचिव, वन सचिव, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व जिला आयुक्त बतौर सदस्य होंगे। यह निगरानी समिति परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने के अलावा विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में डीएफसीसीआईएल की मदद करेगी। वहीं डीएफसीसीआईएल ने भी प्रदेश व जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधकों को उत्तर प्रदेश में नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्ति कर दिया है।

Pioneer, ND_ Dat 10.02.12

PM for freight corridor project on fast track

PIONEER NEWS SERVICE ■ NEW DELHI

Prime Minister Manmohan Singh has directed the Ministers to accord highest priority to the ₹1 lakh crore-Dedicated Freight Corridor Project and asked the State Governments to also do the same.

At a meeting held in the Prime Minister's Office (PMO) recently, the Chief Secretaries and the representatives of the States assured full cooperation of their State Governments in taking forward this important project. It was decided in the meeting that monitoring committees would be constituted by the State Governments to resolve the issues relating to the Dedicated Freight Corridor Project especially land acquisition in an expeditious manner.

The representatives of the nodal authority Dedicated Freight Corridor Cooperation India Limited (DFCCIL) will oversee progress of work with the targeted project completion date being March 2017.

The DFCCIL claimed that 67 per cent of land acquisition has been completed through the Railways Amendment Act, 2008 and the project by and large is on target. The PMO will be closely monitoring progress of the project so that necessary action is taken in a time-bound manner.

The project will connect a land mass over 3,300 km in the country aiming to be a backbone of India's economic transport facility. The Western corridor from Dadri in Uttar Pradesh to Jawaharlal Nehru Port Trust near Mumbai will be 1,499 km and will connect Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra with an exclusive high speed railway track.

The Eastern Dedicated Freight Corridor from Ludhiana to Dankuni will be 1,839 km-long and will connect Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. A major part of Western corridor will be funded with Japanese assistance and nearly two-thirds of the Eastern corridor will be built with World Bank assistance.

The Sonnagar-Dankuni section will be executed on PPP mode. Indian Railways is also investing a substantial amount in the project.

The Hindu, NID, Dated 10.02.12

PMO to monitor dedicated freight corridor project

K. Balchand

NEW DELHI: The Prime Minister's Office (PMO) will henceforth directly monitor the progress of the construction of the Dedicated Freight Corridor — virtually taking the job away from the Railways.

Prime Minister Manmohan Singh on Thursday held a meeting to take stock of the progress, apparently dissatisfied with the role of the Railways which was primarily to monitor the progress of the job — the execution of which had been handed over to the nodal authority, the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL).

At the meeting, it was decided that the PMO would monitor the progress of the project and make timely intervention for the completion of the project by March 2017, stressing that it would prove to be the backbone of the country's economic transport facility.

The Prime Minister directed the States, through which the two dedicated freight corridors pass, to constitute monitoring committees to resolve issues like acquisition of land for completion of the ambitious project on schedule.

The Chief Secretaries of the States concerned and officials of Central ministries who attended the meeting were directed to accord highest priority to the Rs. 1 lakh crore high-speed railway tracks stressing its economic importance.

The DFCCIL claimed it had acquired 67 per cent of the land required and that the project was on target.

The two corridors will cover a length of 3300 km. The Western Corridor from Dadri in Uttar Pradesh to Jawaharlal Nehru Port Trust near Mumbai measuring 1499 km will connect Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. A major portion of the corridor will be financed through Japanese assistance.

The 1839-km-long Eastern Corridor from Ludhiana to Dankuni in West Bengal will connect Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal.

The World Bank will provide assistance for a part of this passageway, while the Sonnagar-Dankuni section will be funded through PPP.

Hindustan, ND, Dat 10.02.12

पीएम की डीएफसी को फास्ट ट्रैक पर लाने की कवायद

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

रेलवे परियोजना

- मनमोहन ने राज्य सरकारों से निगरानी समिति गठित करने को कहा
- डीएफसी परियोजना की समीक्षा में मंत्रालयों से प्राथमिकता देने को कहा

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रेलवे के महत्वाकांक्षी डीएफसी (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) योजना को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए राज्य सरकारों से निगरानी समिति गठित करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने डीएफसी परियोजना की समीक्षा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कहा है कि वह डीएफसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव व प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएफसी परियोजना को संबंधित मंत्रालय सर्वोच्च प्राथमिकता दें, जिससे परियोजना निर्धारित समय 2017 तक पूरा किया जा सके। एक लाख करोड़ लागत की इस परियोजना में तेजी लाने के लिए उन्होंने राज्यों से निगरानी समिति बनाने को कहा है। राज्यों की निगरानी समितियां डीएफसी से जुड़ी समस्याएं विशेषकर भूमि अधिग्रहण का निपटारा तेजी से करेंगी। पीएमओ पहले से ही परियोजना की निगरानी कर रहा है। विदित हो कि डीएफसी परियोजना के लिए 67 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। पश्चिमी व पूर्वी डीएफसी के तहत 3300 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी।

Pol & Bus. Daily, ND, Dt 10.02.12

Manmohan accords top priority for Dedicated Freight Corridor project

PBD BUREAU

NEW DELHI FEB 09

PRIME minister Manmohan Singh has accorded top priority for Dedicated Freight Corridor (DFC) Project costing nearly Rs 1,00,000 crore.

The Prime Minister has directed that the DFC Project should be given the highest priority by Central Ministries and urged the State Governments to also do so, according to a statement issued by the Prime Minister office on Thursday.

In a meeting held in the Prime Minister's Office, the Chief Secretaries and the representatives of the States assured the full cooperation of their state governments in taking forward this important project.

The project will connect a land mass over 3300 kilometers in the country and could prove to be a backbone of India's economic transport facility. The Western corridor from Dadri in Uttar Pradesh to Jawaharlal Nehru Port Trust near Mumbai will be 1499 kilometers and will connect Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra with an exclusive high speed railway track. The Eastern Dedicated Freight Corridor from Ludhiana to Dankuni will be 1839 kilometer long and will connect Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. A major part of Western corridor will be funded with Japanese assistance and nearly two third of the Eastern corridor will be built with World Bank assistance. The Sonnagar- Dankuni section will be executed on PPP mode. Indian Railways is also investing a substantial amount in the Project.

It was decided that Monitoring Committees will be constituted by the State Governments to resolve the issues relating to the Dedicated Freight Corridor project especially land-acquisition in an expeditious manner. The representatives of the nodal authority Dedicated Freight Corridor Cooperation India Limited (DFCCIL) will be overseeing progress of work with the targeted project completion date being March 2017.

The DFCCIL has said that 67% of the land-acquisition has been completed through the Railway Amendment Act 2008 and as of now the project by and large is on target. The Prime Minister's Office will be closely monitoring progress of the project so that necessary action is taken in a time-bound manner.

The Indian Express, N.D., Date 10.02.12

PM puts freight corridor project on fast track

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 9

PRIME Minister Manmohan Singh has intervened to make sure the ambitious dedicated freight corridor project does not miss its March 2017 deadline due to constraints like land acquisition in states and bureaucratic hurdles at various Central ministries.

Calling the DFC a project of "highest priority", Singh has assigned the job of monitoring the progress of the project to the PMO. This was after he held a review meeting of the project on Thursday attended by the top brass of the Dedicated Freight Corridor Cooperation India Limited (DFCCIL), chief secretaries and representatives of states where the corridors' routes are marked.

Sources said Railway Minister Dinesh Trivedi, during his meeting with the PM last week, communicated his concerns about land acquisition issues faced by the corridor, which, at Rs 1 lakh crore, will be one of the biggest infrastructure projects in the country spanning 3300 km across various states.

Pioneer, ND, Dt 10.02.12

PM for freight corridor project on fast track

PIONEER NEWS SERVICE ■ NEW DELHI

Prime Minister Manmohan Singh has directed the Ministers to accord highest priority to the ₹1 lakh crore-Dedicated Freight Corridor Project and asked the State Governments to also do the same.

At a meeting held in the Prime Minister's Office (PMO) recently, the Chief Secretaries and the representatives of the States assured full cooperation of their State Governments in taking forward this important project. It was decided in the meeting that monitoring committees would be constituted by the State Governments to resolve the issues relating to the Dedicated Freight Corridor Project especially land acquisition in an expeditious manner.

The representatives of the nodal authority Dedicated Freight Corridor Cooperation India Limited (DFCCIL) will oversee progress of work with the targeted project completion date being March 2017.

The DFCCIL claimed that 67 per cent of land acquisition has been completed through the Railways Amendment Act, 2008 and the project by and large is on target. The PMO will be closely monitoring progress of the project so that necessary action is taken in a time-bound manner.

The project will connect a land mass over 3,300 km in the country aiming to be a backbone of India's economic transport facility. The Western corridor from Dadri in Uttar Pradesh to Jawaharlal Nehru Port Trust near Mumbai will be 1,499 km and will connect Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra with an exclusive high speed railway track.

The Eastern Dedicated Freight Corridor from Ludhiana to Dankuni will be 1,839 km-long and will connect Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. A major part of Western corridor will be funded with Japanese assistance and nearly two-thirds of the Eastern corridor will be built with World Bank assistance.

The Sonnagar-Dankuni section will be executed on PPP mode. Indian Railways is also investing a substantial amount in the project.

Jansatta, ND. Dat 13.02.12

मालवाहक रेल गलियारे के 2014 तक शुरू होने की उम्मीद

नई दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा)। रेल विभाग की महत्त्वाकांक्षी परियोजना 66 किलोमीटर लंबे मालवाहक गलियारे की निगरानी अब प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। इसके यातायात के लिए 2014 तक खुलने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि मुगलसराय और सोननगर के बीच का पूर्वी गलियारा 2014 तक शुरू हो सकता है। इस गलियारे का निर्माण कार्य अगले साल दिसंबर तक पूरा हो सकता है।

योजना लक्ष्य के मुताबिक, पूर्वी गलियारे में लुधियाना और दानकुनी के बीच और पश्चिमी गलियारे में दादरी व मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच का 3,300 किलोमीटर लंबा मालवाहक गलियारा 2017 तक पूरा होना है। इनके निर्माण पर 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस परियोजना से जहां एक तरफ आर्थिक वृद्धि की गति मिलेगी वहीं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ने वाले स्वर्ण चतुर्भुज के आस-पास उच्च क्षमता वाला नेटवर्क होने से रेल को अपनी परिवहन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। फिलहाल इन मार्गों पर सिर्फ 16 फीसद रेल नेटवर्क है। लेकिन कुल 50 फीसद माल ढुलाई इस नेटवर्क के जरिए होती है।

सूत्रों ने कहा कि 66 किलोमीटर खंड में निर्माण कार्य चल रहा है। पश्चिमी गलियारे में 52 पुलों पर भी काम चल रहा है। पिछले हफ्ते इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संबद्ध राज्यों और केंद्रीय विभागों को निर्देश दिया था कि वे इस परियोजना को प्राथमिकता दें और काम तेज करें। इस परियोजना की निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा।

सूत्रों ने बताया कि जिन छह राज्यों को इस परियोजना से फायदा होना है उनमें से तीन के मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल थे। इनके अलावा रेल बोर्ड के अध्यक्ष विलय मित्तल और अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी भी शामिल थे। भूमि अधिग्रहण के मामले पर बारीकी से विचार किया गया। राज्य सरकारें निगरानी समिति की स्थापना करेंगी ताकि भूमि अधिग्रहण विशेष तौर पर तेजी से किया जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि प्रतिबद्ध माल गलियारे का लक्ष्य है सड़क के जरिए होने वाली माल ढुलाई का बोझ कम किया जा सके और कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। मौजूदा रेल नेटवर्क डीजल और बिजली दोनों किस्म के ईंजन पर निर्भर है। लेकिन प्रस्तावित गलियारे पर केवल बिजली से चलने वाली ईंजन ही चलेंगी। इससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा।

Business Standard, ND. Dat 13.03.12

पीएमओ करेगा मालवाहक गलियारे की निगरानी!

भाषा
नई दिल्ली, 12 फरवरी

भारतीय रेल की महत्वकांक्षी 66 किलोमीटर लंबे मालवाहक गलियारा परियोजना की निगरानी अब प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। यह रेल मार्ग वर्ष 2014 तक शुरू होने की संभावना है।

सूत्रों ने बताया कि मुगलसराय और सोननगर के बीच का पूर्वी गलियारा 2014 तक चालू हो सकता है। और इस गलियारे का निर्माण कार्य अगले साल दिसंबर तक पूरा हो सकता है। योजना लक्ष्य के मुताबिक पूर्वी गलियारे में लुधियाना और दानकुनी के बीच तथा पश्चिमी गलियारे में दादरी व मुंबई के पास स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच का मालवाहक गलियारा 2017 तक पूरा होना है। इनके निर्माण पर 80,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले, स्वर्ण चतुर्भुज के आस-पास उच्च क्षमता वाला नेटवर्क होने से रेल को अपनी परिवहन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

Telegraph, Ranchi, Dat 08.03.12

Eastern rail corridor on fast track

JAYANTA ROY CHOWDHURY & R. SURYAMURTHY

New Delhi, March 4: A 66km stretch of the eastern freight corridor, the showcase project of Indian Railways to attract global investors, is likely to open in early 2014.

Civil work for the project, between Mughalsarai in Uttar Pradesh and Sonnagar in Bihar, is likely to be completed by the end of next year, sources said.

The Rs 24,000-crore eastern corridor is expected to cover 1,839km, from Ludhiana in Punjab to Dankuni near Calcutta, linking industrial towns and mines with the eastern ports. The project is being monitored by the Prime Minister's Office.

Nearly two-third of this corridor will be built with World Bank fund. The Sonnagar-Dankuni section will be executed on a public-private partnership mode. Indian Railways is also investing a substantial amount.

The World Bank will provide $2.7 billion in three tranches: $790 million for Ludhiana-Khurja (397 km), $975 million for Khurja-Kanpur (343km) and $1.05 billion for Kanpur-Mughalsarai (390km).

The rail board has set 2015 as the deadline for the completion of the corridor, which will carry iron, coal, cement and other minerals from Jharkhand, Bihar and Bengal to other parts of the country.

The Japanese government is funding the Rs 26,000-crore western freight corridor, linking Delhi with Mumbai. Work has already started on the project, which is expected to be a money spinner linking large industrial estates with ports in Gujarat and Maharashtra.

According to a study by RITES, the projected traffic on the two dedicated freight corridors in 2016-17 is 75.60 million tonnes, which is likely to increase 20 per cent to 91.33 million tonnes by 2021-22.

FREIGHT FUTURE

Eastern freight corridor

- Project to cover 1,839km, from Ludhiana in Punjab to Dankuni near Calcutta
- World Bank to fund two-thirds of the Rs 24,000-crore project; it will give $2.7 billion in three tranches
- 2015 set as deadline for completing project
- Corridor to carry iron, coal and other minerals from Jharkhand, Bihar and Bengal to other parts of the country

Western freight corridor

- 1,483km corridor to link Delhi with Mumbai, running through Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra
- Japan is funding 60% of the construction cost of the Rs 26,000cr project

Projected traffic on two freight corridors in 2016-17 is 75.60 million tonnes

Between April 2011 and Jan 2012, railways earned Rs 55,361cr as freight revenue

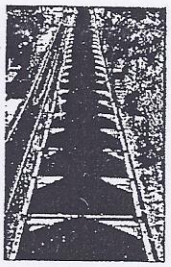

More ventures

Besides the freight corridors, the railways are looking to join hands with private players in laying commercial lines to move coal, iron ore and other raw materials for industrial customers.

"We have to meet the needs of the customers...we have signed a deal with SAIL, Coal India, private companies and Chhattisgarh to set up three railway corridors to evacuate coal from greenfield mines in that state," railway minister Dinesh Trivedi told The Telegraph.

"We found out on a visit to that state that new mines had sprung up in north Chhattisgarh but these were not linked to the rest of the country. Which is were we came in and signed a deal," he said.

The three corridors in Chhattisgarh — east corridor linking Bhupdevpur to the Korba industrial hub, north section linking Korba with Surajpur and an east-west link between Gevra and Pendra — will be funded through special purpose vehicles with investment from state-run and private firms as well as the state government.

Freight constitutes a major portion of the railways' revenues. Between April 2011 and January 2012, the railways earned Rs 55,361 crore as freight revenue, a 9.7 per cent increase over the year-ago period. It earned Rs 69,000 crore in the last fiscal.

The railways need higher earnings from freight to meet its modernisation and safety plans. It aims to ramp up freight revenue by following a two-pronged strategy of increasing the turnover ratio on tracks and hiking charges.

Improved turnover ratio means more freight trains will move along a single stretch during a specified period. A marginal increase in rates is a possibility for goods that can afford a hike such as coal.

Trivedi's aides say a hike in freight charges is on the cards as the gross budgetary support for the railways is not expected to be much higher than last year's Rs 20,000 crore.

Telegraph, ND, Dat 06.03.12

Eastern rail corridor on fast track

JAYANTA ROY CHOWDHURY & R. SURYAMURTHY

New Delhi, March 4: A 66km stretch of the eastern freight corridor, the showcase project of Indian Railways to attract global investors, is likely to open in early 2014.

Civil work for the project, between Mughalsarai in Uttar Pradesh and Sonnagar in Bihar, is likely to be completed by the end of next year, sources said.

The Rs 24,000-crore eastern corridor is expected to cover 1,839km, from Ludhiana in Punjab to Dankuni near Calcutta, linking industrial towns and mines with the eastern ports. The project is being monitored by the Prime Minister's Office.

Nearly two-third of this corridor will be built with World Bank fund. The Sonnagar-Dankuni section will be executed on a public-private partnership mode. Indian Railways is also investing a substantial amount.

The World Bank will provide $2.7 billion in three tranches: $790 million for Ludhiana-Khurja (397 km), $975 million for Khurja-Kanpur (343km) and $1.06 billion for Kanpur-Mughalsarai (390km).

The rail board has set 2015 as the deadline for the completion of the corridor, which will carry iron, coal, cement and other minerals from Jharkhand, Bihar and Bengal to other parts of the country.

The Japanese government is funding the Rs 26,000-crore western freight corridor, linking Delhi with Mumbai. Work has already started on the project, which is expected to be a money spinner linking large industrial estates with ports in Gujarat and Maharashtra.

According to a study by RITES, the projected traffic on the two dedicated freight corridors in 2016-17 is 75.60 million tonnes, which is likely to increase 20 per cent to 91.33 million tonnes by 2021-22.

FREIGHT FUTURE

Eastern freight corridor

- Project to cover 1,839km, from Ludhiana in Punjab to Dankuni near Calcutta
- World Bank to fund two-thirds of the Rs 24,000-crore project; it will give $2.7 billion in three tranches
- 2015 set as deadline for completing project
- Corridor to carry iron, coal and other minerals from Jharkhand, Bihar and Bengal to other parts of the country

Western freight corridor

- 1,483km corridor to link Delhi with Mumbai, running through Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra
- Japan is funding 80% of the construction cost of the Rs 26,000cr project

Projected traffic on two freight corridors in 2016-17 is 75.60 million tonnes

Between April 2011 and Jan 2012, railways earned Rs 55,381cr as freight revenue

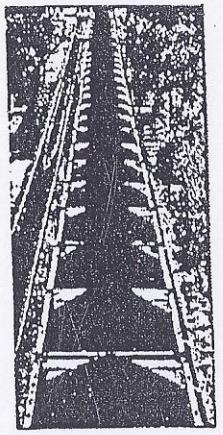

More ventures

Besides the freight corridors, the railways are looking to join hands with private players in laying commercial lines to move coal, iron ore and other raw materials for industrial customers.

"We have to meet the needs of the customers...we have signed a deal with SAIL, Coal India, private companies and Chhattisgarh to set up three railway corridors to evacuate coal from greenfield mines in that state," railway minister Dinesh Trivedi told The Telegraph.

"We found out on a visit to that state that new mines had sprung up in north Chhattisgarh but these were not linked to the rest of the country. Which is were we came in and signed a deal," he said.

The three corridors in Chhattisgarh — east corridor linking Bhupdevpur to the Korba industrial hub, north section linking Korba with Surajpur and an east-west link between Gevra and Pendra — will be funded through special purpose vehicles with investment from state-run and private firms as well as the state government.

Freight constitutes a major portion of the railways' revenues. Between April 2011 and January 2012, the railways earned Rs 55,381 crore as freight revenue, a 9.7 per cent increase over the year-ago period. It earned Rs 69,000 crore in the last fiscal.

The railways need higher earnings from freight to meet its modernisation and safety plans. It aims to ramp up freight revenue by following a two-pronged strategy of increasing the turnover ratio on tracks and hiking charges.

Improved turnover ratio means more freight trains will move along a single stretch during a specified period. A marginal increase in rates is a possibility for goods that can afford a hike such as coal.

Trivedi's aides say a hike in freight charges is on the cards as the gross budgetary support for the railways is not expected to be much higher than last year's Rs 20,000 crore.

Pioneer, ND, Dated 04.03.12

UP polls over, babus get on with freight corridor land deals

PMO had sought monitoring panel for Centre-State coordination

STAFF REPORTER ▪ NEW DELHI

With a long stretch of the dedicated freight corridor to cross through Uttar Pradesh, the State administration taking a time out from the busy poll schedule deliberated upon to expedite the work pertaining to land acquisition and compensation.

On the directions of PMO, top officials of UP including the Chief Secretary, Revenue Secretary, Secretary PWD and Secretary Forest called on a meeting with the DFCC officials last week to resolve the land acquisition issues in the State. While the DFCC decided to appoint the Project Managers as Nodal Officers, the State administration too appointed officers to coordinate with the DFCC Monitoring Committee, which was formed on the directions of the PMO last month.

With several infrastructural projects embroiled in controversies surrounding land acquisition, the PMO has directed the State Governments to establish a monitoring committee that can co-ordinate well at both the State and district levels to avoid any complication in the over ₹80,000 crore ambitious project. It is envisaged that the dedicated corridors will be fully operational over their entire length of about 3,300 kilometres by 2017.

The PMO had asked the Chief Secretaries of the States — UP, Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra - to coordinate and facilitate the construction of the Western Corridor. These are the States under whose jurisdiction the western corridor falls.

"Since of late, many of the projects have either been stalled or put on hold due to land acquisition problem. The Government does not want to waste time on the Dedicated Freight Corridor. It is an ambitious project and this will help on several fronts including price inflation, put on tracks fast moving passenger trains and movement of goods within a stipulated and desired time. "Just like the Golden Quadrilateral project, the DFCC too has a significant role to play in developing a better economy within the country," said a top Railway Ministry source.

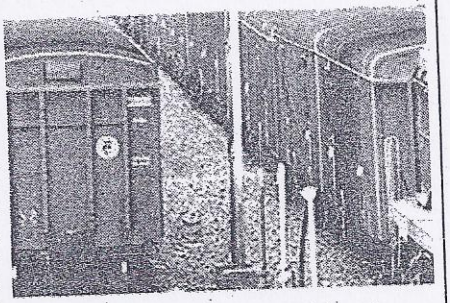

In the first phase, DFCCIL will be constructing two corridors — the Western DFC and Eastern DFC — spanning a total length of about 3,300-kilometres. The Western Corridor will traverse the distance from Dadri to Mumbai, passing through States of Delhi, Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. The Eastern Corridor, starting from Ludhiana in Punjab will pass through the States of Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and terminate at Dankuni in West Bengal.

Amar Ujala, ND, Dated 15.03.12

माल ढुलाई के लिए बंदरगाहों से जुड़ेगी रेलवे

3300 किलोमीटर लंबा माल ढुलाई गलियारा बनाया जाएगा जो कि देश के पूर्व, पश्चिम और उत्तरी भागों को जोड़ेगा। इसके लिए 10700 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी।

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए रेलवे की बंदरगाहों पर परिवहन सुविधा मुहैया कराने की योजना का इस साल से श्रीगणेश होगा। इसके तहत पूर्वी व पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के 1000 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रेल बजट में दो डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर (समर्पित माल गलियारा) बनाने का प्रस्ताव किया गया है। सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक 3300 किलोमीटर से अधिक लंबी है। इसमें देश के पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी राज्य शामिल हैं।

लोकसभा में रेल बजट प्रस्तुत करते हुए रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने बताया कि सड़क मार्गों पर बंदरगाह से माल ढुलाई के लोड को कम करने के लिए रेलवे ने बंदरगाहों तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनायी है। इसके तहत पहले चरण में दो प्रमुख बंदरगाहों को रेलवे से जोड़ा जाएगा। इसमें लुधियाना से दानकुनी और दूसरा दादरी से जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह हैं।

त्रिवेदी के मुताबिक इन परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता से पूरा किया जाएगा। इनमें से एक 3300 किलोमीटर लंबा माल ढुलाई गलियारा बनाया जाएगा जो कि देश के पूर्व, पश्चिम और उत्तरी भागों को जोड़ेगा। इस गलियारे को बनाने के लिए रेलवे को लगभग 10700 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। खास बात यह है कि अभी तक इस परियोजना के लिए रेलवे 6500 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर चुकी है।

रेल मंत्री के मुताबिक इस कोरिडोर के तहत सिविल और ट्रैक कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर पर लगभग 1000 किलोमीटर के लिए इस साल ठेका दे दिया जाएगा।

डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर

1. विश्व बैंक की सहायता से बनेंगे दो नए डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर
2. दादरी-मुंबई और लुधियाना-दानकुनी कोरिडोर का काम होगा तेज
3. पूर्वी व पश्चिमी फ्रेट कोरिडोर के लिए इस साल शुरू होगी निविदा प्रक्रिया